



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 11, 2013/चैत्र 21, 1935

No. 68]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 11, 2013/CHAITRA 21, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2013

विषय:- पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लीयर प्लोट ग्लास के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/25/2012.—डीजीएडी : समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसार मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मै. एच एन जी प्लोट ग्लास लि. और मै. सेण्ट गोबैन ग्लास इंडिया लिमिटेड ने पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लीयर प्लोट ग्लास (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. और यतः, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के घरेलू उद्योग को 'क्षति' के तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं; अतः प्राधिकारी, एतदपश्चात कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच करने और कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने, जो यदि वसूली गई तो, घरेलू उद्योग को होने वाली 'क्षति' को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत पाटनरोधी जांच प्रारंभ करते हैं।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. यह आवेदन पत्र घरेलू उद्योग की ओर से मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लि., मै. एच एन जी प्लोट ग्लास लिमिटेड एवं मै. सेण्ट गोबैन ग्लास इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। उपर्युक्त घरेलू उत्पादकों के अलावा मै. असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड (एआईएस) और गुजरात गार्डियन लिमिटेड (जीजीएल) भी संबद्ध वस्तु का उत्पादन करते हैं। चूंकि ए आई एस, संबद्ध देशों से आयातकर्ता है और जी जी एल का सऊदी अरेबिया में एक संबंधित पक्षकार है, अतः प्राधिकारी ने आवेदनकर्ताओं को घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में माना है तथा जीजीएल एवं एआईएस को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना है। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मै. गोल्ड

प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मै. एच एन जी प्लोट ग्लास लिमिटेड और मै. सेण्ट गोबैन ग्लास लिमिटेड समान वस्तु के भारतीय उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करते हैं और इसलिए वे समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन के भारी भाग का उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी हैं। अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियम 2 (ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है तथा आवेदक नियम 5(3) और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग के मानदंड को पूरा करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद

4. इस आवेदनपत्र में विचाराधीन उत्पाद “4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों शामिल) तक की सामान्य मोटाई का क्लीयर फ्लोट ग्लास” है, जो बी आई एस 14900: 2000 के अनुसार अभिहित मोटाई है (जिसे एतदपश्चात ‘संबद्ध वस्तु’ या ‘विचाराधीन उत्पाद’ कहा गया है)। संबद्ध वस्तु का उपयोग सस्पेंडेड सीलिंग और विभाजन अनुप्रयोगों में आंतरिक निर्माण के लिए किया जाता है। संबद्ध वस्तु को अध्याय शीर्षक 70 “ग्लास एवं ग्लासवेअर” के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 8 अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 70051090 है यद्यपि इसे विभिन्न उपशीर्षकों जैसे 7003, 7004, 7005, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 और 7020 आदि के अंतर्गत वर्गीकृत एवं आयात किया जा रहा है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह जांच के उत्पाद दायरे में किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

5. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु जिसका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान है। संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद तथा पाटित आयातों की तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता, कार्य अथवा उपयोग में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस कारण, नियमों के अंतर्गत उन्हें “समान वस्तु” के रूप में माना जाना चाहिए। अतः, वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए, आवेदकों द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु को ‘समान वस्तु’ के रूप में माना जा रहा है।

शामिल देश

6. वर्तमान जांच में शामिल देश पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

सामान्य मूल्य

7. आवेदक ने इन संबद्ध देशों के बारे में सामान्य मूल्य का निर्धारण यह उल्लेख करते हुए किया है कि वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं और न ही कोई सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर प्रथम दृष्टया विचार आवेदक द्वारा यह जांच शुरू किए जाने के उद्देश्य से यथा उपलब्ध कराए गए सामान्य मूल्य के आधार पर किया है।

निर्यात कीमत

8. आवेदक ने निर्यात कीमत का दावा इन्फोइराइब इंडिया प्रा. लिमिटेड, कोलकाता से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया है। कीमत समायोजन का दावा करने की अनुमति समुद्री भाड़ा, समुद्रिक बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, कमीशन, पत्तन रखरखाव, और पत्तन प्रभारों के आधार पर निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए दी गई थी। पाटन रोधी जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।

पाटन मार्जिन

9. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना फैक्टरी बाह्य स्तर पर की गई है जिसमें संबद्ध देशों के बारे में प्रथम दृष्टया महत्वपूर्ण पाटन मार्जिन दर्शाया गया है। इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य, फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत से पर्याप्त उच्च है, इससे, प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का भारत की बाजारों में पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन को न्यूनतम से ऊपर आकलित किया जाता है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

10. आवेदक ने पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि, कीमत अधोरदन, कीमत निग्रहण, कम कीमत पर बिक्री और घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता, लगाई गई पूंजी पर अर्जन, नकदी प्रवाह, बाजार हिस्सा, उत्पादन, क्षमता उपयोग आदि में गिरावट के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप होने वाली ‘क्षति’ के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। पाटनरोधी जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई जा रही क्षति के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

जांच की अवधि (पी ओ आई)

11. आवेदकों द्वारा यथा प्रस्तावित जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2011 से 30 सितम्बर, 2012 (12 माह) थी। तथापि, अधिक अद्यतन आंकड़ों के आधार पर अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी ने जांच की अवधि का निर्धारण 1 अक्टूबर, 2011 से 31 दिसम्बर, 2012 (15 माह) किया है। क्षति का निर्धारण करने के लिए विगत तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल, 2009 मार्च 2010, अप्रैल, 2010 – मार्च, 2011, अप्रैल, 2011 – मार्च, 2012 तथा क्षति की अवधि पर विचार किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उनके दूतावासों के जरिए, भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है और उसे निम्नलिखित पते पर प्रेषित कर सकता है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय****वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय****वाणिज्य विभाग****उद्योग भवन****नई दिल्ली-110011****समय-सीमा**

13. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई हेतु कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन) के भीतर पहुंच जाना चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) में दी गई शर्तों के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राधिकारी को प्रदान कराई गई किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत करेंगे और ऐसी सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार के विचार से यदि उक्त सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो उसके कारणों का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उस तक पहुंच को मना करता है अथवा तर्क संगत अवधि के अंतर्गत आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में बाधा उत्पन्न करता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार से ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

15. उपर्युक्त पैरा में किसी बात का उल्लेख होते हुए भी यदि प्राधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का दावा आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अथवा इसके प्रकटन को सामान्यीकृत ढंग से या सार रूप में प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

16. पाटनरोधी अधिनियम के नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

17. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**New Delhi, the 11th April, 2013

Subject : Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of Clear Float Glass originating in or exported from Pakistan, Saudi Arabia and UAE.

No.14/25/2012-DGAD.—M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s HNG Float Glass Ltd. and M/s Saint-Gobain Glass India Ltd., have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Clear Float Glass (hereinafter also referred to as the

subject goods), originating in or exported from Pakistan, Saudi Arabia and United Arab Emirates (UAE) (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Domestic Industry & 'Standing'

3. The Application has been filed by M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s HNG Float Glass Ltd. and M/s Saint-Gobain Glass India Ltd., on behalf of the domestic industry. Apart from the above domestic producers M/s Asahi India Glass Limited (AIS) and Gujarat Guardian Ltd. (GGL) also produce the subject goods. Since AIS is an importer from the subject countries and GGL has its related party in Saudi Arabia, the Authority proceeds to consider the applicant eligible as part of the domestic industry and does not consider AIS and GGL as part of the domestic industry. As per the evidence available on record, the production of M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s HNG Float Glass Ltd. and M/s Saint-Gobain Glass India Ltd., accounts for a major proportion of the total domestic production of the like article and is more than 50% of Indian production of the like article. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

4. The product under Consideration in the present application is "Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive)", the nominal thickness being as per BIS14900:2000 (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "Product under Consideration"). The subject goods are used in interior construction in suspended ceiling and partition applications. The subject goods are classified under Chapter Heading 70 "Glass and glassware". The classification at the 8-digit level is 70051090 even though the same are being classified and imported under various sub-headings like 7003, 7004, 7005, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 and 7020 etc. The customs classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope of the investigation.

Like Article

5. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Countries involved

6. The countries involved in the present investigation are Pakistan, Saudi Arabia and United Arab Emirates.

Normal Value

7. The applicant has constructed the normal values in respect of these subject countries stating that neither they were able to get any documentary evidence or reliable information with regard to domestic prices of the subject goods in the subject countries nor the same are available in the public domain. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed values as made available by the applicant for the purpose of initiating this investigation.

Export Price

8. The applicant has claimed export prices on the basis of data obtained from Infodrive India Pvt. Ltd, Kolkata. Price adjustments have been allowed on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, commission, port handling and port charges, etc. to arrive at the net export price. There is sufficient evidence of the export prices of the subject goods from the subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

Dumping Margin

9. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which shows prima facie significant dumping margin in respect of the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

Injury and Causal Link

10. The applicant has furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price underselling, price suppression and decline in profitability, return on capital employed, cash flow, market share, production, capacity utilization etc. of the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Period of Investigation (POI)

11. The Period of investigation, as proposed by the applicants, was from 1st October 2011 to 30th September, 2012 (12 months). However, to make required analysis on the basis of more updated data, the Authority has determined the POI as 1st October, 2011 to 31st December, 2012 (15 months). For the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. April 2009-March 2010, April 2010 – March 2011, April 2011 - March 2012 and the period of investigation will be considered.

Submission of information

12. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers/users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file required information in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce, Udyog Bhawan,
New Delhi -110011.**

Time limit

13. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

Submission of Information on Non-Confidential basis

14. In terms of Rule 6(7) of the Anti-dumping Rules, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

15. Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

Inspection of Public File

16. In terms of Rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

17. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

J.S. DEEPAK, Designated Authority